'वन ट्रिलियन डालर अर्थव्यवस्था के लिए अधिक निवेश की जरूरत'

राब्यू, जागरण● लखनऊ : वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने गुरुवार को एक ट्रिलियन डालर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य की समग्र रणनीति और वित्त विभाग के नेतृत्व वाले प्रमुख क्षेत्रों के प्रदर्शन की समीक्षा की। मंत्री ने कहा कि इसके लिए और अधिक निवेश व परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने की जरूरत है। उन्होंने कई प्रमुख क्षेत्रों में निरंतर प्रयास के महत्व पर बल दिया। इनमें तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग, बेहतर अनुपालन, नागरिक सेवाओं पर ध्यान, प्रवर्तन उपाय तथा लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से विभागीय क्षमता का विकास शामिल है।

वित्त मंत्री की समीक्षा बैठक में वाणिज्यिक कर, आबकारी, स्टांप और पंजीकरण, खनन और परिवहन विभाग शामिल हुए। मंत्री ने कहा कि पिछले पांच-छह वर्षों में राज्य के कर राजस्व में काफी वृद्धि हुई है। उन्होंने अब तक की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। अधिकारियों ने वन ट्रिलियन डालर अर्थव्यवस्था के तहत प्रगति का मूल्यांकन पेश किया। चर्चा के दौरान कहा गया कि विभिन्न क्षेत्रों में विकास को गति देने के लिए निवेश भी जरूरी है। बताया गया कि प्रदेश सरकार ने हालिया वर्षों में पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि की है।

प्रदेश के विकास में राज्य कर विभाग का बड़ा योगदान

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि प्रदेश के विकास में राज्य कर विभाग का बड़ा योगदान है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश व प्रदेश की कर व्यवस्था को और सरल किया है। इसकी वजह से राजस्व संग्रह बढ़ा है और उत्तर प्रदेश अतिरिक्त राजस्व वाले प्रदेशों में शामिल हो गया है। उन्होंने कहा कि विभाग में संवर्ग पुनर्गठन की मांग को हल करवाने के लिए वह मुख्यमंत्री से बात करेंगे। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में गुरुवार को उप्र राज्य कर सेवा संघ के दो दिवसीय वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन करने के बाद वित्त मंत्री ने कहा कि नए वित्तीय वर्ष में प्रदेश के अनुमानित बजट में 50 प्रतिशत राजस्व का हिस्सा अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतन व कर्ज चुकाने में खर्च हो रहा है। राज्य कर आयुक्त डा .आदर्श सिंह ने कहा कि वह संघ की मांगों को शासन के सामने रखेंगे।

बैठक में बताया गया कि बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लगभग दो लाख करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। फरवरी 2024 में आयोजित भूमिपूजन समारोह के दौरान लगभग 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश की शुरुआत हुई है।